शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 9 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 24 – 3 मार्च 2025 मूल्य पांच रूपये

सरकार ने न किसी मन्दिर से कोई पैसा लिया न भविष्य में लेने का कोई विचार है:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल।उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री छोटी काशी अंतरराष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव-2025 में देवी-देवताओं के साथ निकली राज देव माधो राय की पारंपरिक 'मध्य जलेब' शोभा यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने राज देवता राज माधो राय मंदिर में पूजा-अर्चना की। मध्य जलेब राज माधो राय मंदिर से शुरू होकर पब्दल मैदान में संपन्न हुई। खिली धूप में हजारों की संख्या में लोग जलेब में शामिल हुए। शोभायात्रा में देवी-देवताओं के साथ आए देवलु पारंपरिक परिधान पहने अपने स्थानीय देवताओं के साथ नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बता दें, महोत्सव में पूरे क्षेत्र से 200 से अधिक देवी- देवता पधारे हैं।

पब्दल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी शिवरात्रि महोत्सव हमारी आस्था का प्रतीक है। शिवरात्रि महोत्सव में इस देवभूमि में देवताओं का समागम पूरे भारत में हिमाचल को पहचान दिलाता है। मंडी शिवरात्रि हो या कुल्लू दशहरा और मिंजर, यहां आयोजित होने वाले मेले हमारे प्रदेश की शान हैं। इन मेलों में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

उन्होंने इस अवसर पर इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के संचालन में मंदिरों के चढ़ावे का पैसा लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर में आस्था रखते हैं। मन्दिरों को पैसा उपलब्ध करवाते हैं। मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकारी कोष से पैसा उपलब्ध करवाया जाता है। किसी मन्दिर का पैसा सरकार ने न तो लिया है और न ही भविष्य में किसी मन्दिर से पैसा लेने का कोई विचार है। कुछ लोगों की विकृत मानसिकता से यह गलत धारणा फैलाई जा रही है। मन्दिरों का रखरखाव, जोर्णोद्धार करके सर्किट तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मंडी शिवरात्रि की अंतरराष्ट्रीय पहचान कायम करने लिए विधायक चन्द्रशेखर और उपायुक्त सहित उनकी सारी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कि यहां पर आयोजित ब्यास आरती अब लंबे समय तक आयोजित की जाएगी और आने वाले समय में प्रयास किया जाएगा की यहां ब्यास आरती घाट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मंडी

शिवरात्रि महोत्सव को नई ऊंचाईयों देने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि भाषा विभाग हिमाचल में जितने भी त्यौहार होते हैं, उनकी तारीखों और कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर एक सूची तैयार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को इन त्यौहारों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में समुचित मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेले में व्यय होने वाली निश्चित राशि निर्धारित करके स्थानीय कलाकारों पर व्यय की जा रही है।

परिवहन सुविधाओं में विस्तार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिमला में 2000 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंडोह में स्थापित रोपवे आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। कुल्लू में दो रोपवे स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ों को इस ढंग से रोपवे से जोड़ा जाएगा ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां पहुंचे।

प्रदेश की बजाये मित्र सलाहकार और सीपीएस है सरकार की प्राथमिकता:जयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी ब्यान में कहा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री दस्तावेज़ होने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं। उनकी पार्टी की मुखिया और उनके मंत्री भी यह मान रहे हैं की मंदिरों से पैसा मांगा जा रहा है लेकिन मुख्यमंत्री हर बात को हवा में उड़ाने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। दो साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में आम जनमानस कहीं नहीं है। नहीं उनके हित के लिए किसी भी काम में सरकार द्वारा कोई तत्परता दिखाई गई है। वर्तमान सरकार का सारा ध्यान अपने मित्रों, सलाहकारों और मुख्य संसदीय सचिवों पर है। जिन पर धड़ल्ले से करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। नियम विरुद्ध संसदीय सचिव प्रदेश पर थोप कर एक तरफ सरकार ने जहां आम आदमी की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए का बोझ सरकार पर डाला तो वहीं उन्हें बचाने की कानूनी लड़ाई में भी करोड़ों रुपए एक-एक बार की पेशी के लिए वकीलों को दिए गए। जिन दो योजनाओं के लिए सरकार मंदिरों से पैसा मांग रही है उन योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है लेकिन योजना और उसके असली लाभार्थियों के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं रखा है। अभी योजना को चले एक साल भी नहीं हुए और सरकार भगवान के भरोसे आ गई। जबकि पूरे प्रदेश को इन योजना के पोस्टर से भर दिया गया है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार सिर्फ केन्द्र सरकार के द्वारा भेजे जा रहे पैसे का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए विकासात्मक कार्यो के बजट को स्टेट ट्रेजरी में डायवर्ट कर रही है। जिससे सारे के सारे काम ठप पड़े हैं। मुख्यमंत्री और उनके करीबियों की प्राथमिकताओं और लाभ के अनुसार ही यह धनराशि खर्च की जा रही है। पूरे प्रदेश में सरकार यही कर रही है। जहां मित्र मंडली की बात आती है सरकार मिनटों में करोड़ों रुपए का प्रबंध कर लेती है लेकिन जहां आम हिमाचली के हित का मामला होता है वहां पर सरकार विपक्ष और केंद्र सरकार को कोसेगी। या प्रदेश वासियों और भगवान के भरोसे बैठ जाएगी। सरकार इस तरह से अपना-पराया करके नहीं चल सकती है। सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के लोग होने चाहिए ना की मुख्यमंत्री के खास लोग।

सत्ता में आने के बाद से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बस प्रदेश वासियों की जेबें टटोली है। उनको मिल रही सुविधाएं खत्म की है और महंगाई बढ़ाने का काम किया

.....पृष्ठ 1 का शेष

10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के 8वें सत्र का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 10 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश

विधानसभा के 8वें सत्र के शुभारम्भ अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2023-24 को प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। नए स्तरोन्नत नगर निगमों में 66 पद, नगर परिषदों में 3 पद, नव सृजित नगर पंचायतों में 70 पद और शहरी विकास विभाग के निदेशालय में 6 पद भरे जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल संस्थान, चमियाणा में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के लिए दो वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के पद सृजित कर भरने की भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने पारंपरिक कत्था भट्टियों को आईबीआर बायलर युक्त कत्था भट्टियों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की। अब इन्हें राज्य के मुख्य बायलर निरीक्षक के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाना होगा। आईबीआर बायलर के माध्यम से खैर लकड़ी (छाल सहित) को पूरे वर्ष में 5435 से 7500 क्विंटल की सीमा में संसोधित करने की अनुमति होगी।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि महाशिवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति, आत्म-अनुशासन और भक्ति का पर्व है। 'देवभूमि' के नाम से विख्यात हिमाचल प्रदेश में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं। इस पर्व का प्रदेशवासियों के जीवन में अतीव महत्व है। उन्होंने लोगों से शिवरात्रि पर्व को धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाने का आहवान किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री ने डेरा बाबा रुद्रानंद के संस्थापक के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने डेरा बाबा रुद्रानंद के संस्थापक वेदांताचार्य 1008 स्वामी श्री श्री सुग्रीवानंद महाराज जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका स्वर्गवास हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनका निधन लम्बी बीमारी के चलते पीजीआई चंढीगढ़ में हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज जी द्वारा दी गई शिक्षाएं हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति एवं उनके अनुयायियों के प्रति संवदेनाएं व्यक्त की हैं।

छोटी काशी महाशिवरात्रि महोत्सव पर ब्यास आरती का आयोजन

अध्यात्म के रंगों से सराबोर हुआ पंचवक्त्र एवं विपाशा तट

शिमला/शैल। छोटी काशी अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए महाशिवरात्रि की संध्या पर ब्यास

आरती का आयोजन किया गया। मंडी नगर के सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक पंचवद्र मंदिर के सामने पौराणिक नदी विपाशा के तट पर काशी के विद्वान पंडितों की अगवानी में की गई ब्यास आरती ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक रंगों से सराबोर कर दिया। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर, एपीएमसी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया, उपायुक्त एवं छोटी काशी अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष अपूर्व देवगन सहित अन्य गणमान्य एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं देवलु इसके साक्षी बने।

ब्यास आरती के लिए विपाशा एवं सुकेती के संगम पर पांच विशेष मंच तैयार किए गए। काशी से पधारे पुजारियों ने इन मंचों से महा आरती की विधि संपन्न की। इस भव्य एवं अलौकिक आयोजन में सहभागिता जताने के लिए मंडी शहर की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। शहर के लोगों ने घर से एक-एक दीया लाकर महाशिवरात्रि की संध्या को रोशनी के रंगों से भर दिया।

उपायुक्त ने सभी उपस्थित जनों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बार का महाशिवरात्रि महोत्सव इस सदी के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में सदी की रजत जयंती के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए शिवरात्रि महोत्सव में कई नए आयाम जोड़े गए हैं। ब्यास आरती के अलावा इस बार महोत्सव के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को विस्तार देते हुए पांच से अधिक देशों से विशेषतौर पर सांस्कृतिक दल आमंत्रित किए गए हैं। यह दल हिमाचल तथा बाहरी राज्यों से आने वाले अन्य सांस्कृतिक दलों के साथ 28 फरवरी को होने वाली कल्चरल परेड में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त महोत्सव के शुभारंभ एवं समापन अवसर व सांस्कृतिक संध्याओं में भी अपनी प्रस्तुति देंगे।

इस अवसर पर नगर निगम मंडी के महापौर वीरेंद्र भट शर्मा, एच पी एम सी के निदेशक जोगिंदर गुलेरिया, मुख्य सूचना आयुक्त एस एस गुलेरिया, पीमंडलायुक्त ए. साइनामोल, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर, उपमंडलाधिकारी ना. ओमकांत ठाकुर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. मदन कुमार सहित अन्य अधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, देवलु एवं कारदार व अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

रक्छम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये व्यय होंगे 5 करोड़ रुपयेः आर.एस.बाली

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम एचपीटीडीसी के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली ने कहा है कि राज्य सरकार सांगला घाटी के रक्छम गांव में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर की सांगला घाटी में प्राकृतिक सौन्दर्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपये की विकास परियोजना तैयार की है।

इस परियोजना के तहत रक्छम के साथ-साथ बटसेरी और खरोगला में रास्तों की मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा, क्षेत्र में शौचालय, वॉचमैन हट, वुडन हट और वॉच टावर जैसी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सांगला से देबर कांडा होते हुए सांगला कांडा तक ट्रॉली आधारित ट्रेल भी विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षता से समर्पित प्रयास कर रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को विकसित करने में धन की कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि सरकार अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश भर में आवश्यक पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। आने वाले समय में प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास में योगदान देने वाली कई प्रमुख परियोजनाओं को विभिन्न स्थानों पर कार्यान्वित किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रमों से संवरेगा युवाओं का भविष्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी के युग में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कई नए डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का नया डिग्री कोर्स, जिला शिमला के प्रगतिनगर में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, जिला मंडी के राजकीय पॉलिटेक्निक सुंदरनगर में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस तेजी से उभरते हुए क्षेत्र है और वर्तमान परिपेक्ष्य में सामाजिक प्रक्रियाओं को डाटा के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र तथा विभिन्न उद्योगों में एआई और डाटा साइंस कौशल की अत्यधिक मांग है। इन क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इस क्षेत्र से युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के अपार अवसर उपलब्ध होंगे और प्रशिक्षित युवा नवाचार के माध्यम से समाज में सार्थक योगदान प्रदान करेंगे। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को डाटा का विश्लेषण करने और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निर्णय लेने संबंधी ज्ञान प्रदान करने में सहायक साबित होगे।

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी प्रगतिनगर में शुरू किया जा रहा सिविल इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम युवाओं को उच्च वेतन तथा व्यावसायिक रूप से प्रगति करने के अवसर प्रदान करेगा। प्रशिक्षित युवा न्यू एज पाठ्यक्रमों के ज्ञान के माध्यम से अधोसंरचना के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। उन्होंने कहा कि इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आवश्यक स्टाफ उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों से राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

किसानों को लाभान्वित करने के लिये राज्य में 1292 करोड़ रुपये की एचपी शिवा परियोजना का किया जा रहा क्रियान्वयन

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं। प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में 1292 करोड़ रुपये की महत्त्वाकांक्षी एचपी शिवा परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के सात जिलों के 28 खंडों की 6000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर बागवानी, सिंचाई, सोलर बाड़बंदी जैसे कार्य प्रगति पर हैं।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना जिला में अमरूद, संतरे, लीची और पलम जैसे फलों की खेती को प्रोत्साहित कर 15 हजार से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। किसानों को उनके उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

बागवानी मंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत किसानों के खेतों तक बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 162 उठाऊ सिंचाई योजनाएं निर्मित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बागवानों को ड्रिप सिंचाई और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर बाड़बंदी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों और योजना से संबंधित सभी हितधारकों को परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कार्य करने और साइट निरीक्षण कर संबंधित प्रगति की फोटोग्राफी सुनिश्चित करने के लिए कहा।

उन्होंने सभी हितधारकों को कलस्टरों में पर्याप्त कार्यबल और मशीनरी तैनात करने के निर्देश भी दिए तथा कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना में गुणवत्तापूर्ण कार्य करना सुनिश्चित करें और किसानों को पौध रोपण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पौध उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार नवीन प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान इस परियोजना का लाभ उठा सकें।

बैठक में सचिव बागवानी सी. पालरासु, बागवानी तथा जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य हितधारक उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

देवताओं के नजराने में 5 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा:मुख्यमंत्री

शिवधाम के निर्माण के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये आवंटित करेगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी के ऐतिहासिक पड्ल मैदान में एक सप्ताह तक चलने वाले विश्व विख्यात अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी-2025 का औपचारिक रूप से

शुभारम्भ किया। इस महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक उत्सवों की आभा सभी को आकर्षित करती है। महोत्सव में देश-विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु भाग लेते हैं।

हल्की बारिश के बीच पारंपरिक 'शाही जलेब' शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के मुख्य देवताज माधो राय मंदिर में पूजा-अर्चना की। मंदिर से शुरू होकर पड्ल मैदान में संपन्न हुई भव्य शोभायात्र में हजारों श्रद्धालु पारंपरिक परिधान पहने अपने स्थानीय देवताओं के साथ नृत्य करते हुए आगे बढ़े। पूरे क्षेत्र से 200 से अधिक देवी-देवताओं ने इस जीवंत कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिससे इसकी आध्यात्मिक भव्यता और बढ़ गई।

मुख्यमंत्री ने सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप पगड़ी समारोह में भाग लिया। इसके उपरान्त उन्होंने पड्ल मैदान में विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया और इसमें गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने मेला समिति द्वारा प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से सूखे के बाद आखिरकार क्षेत्र में बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने किसानों की प्रार्थना सुनी और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है।

उन्होंने मंडी शिव धाम परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की और दो वर्ष के भीतर इसे पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भव्य शिव धाम दूर-दूर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उन्होंने देवताओं के नजराने में 5 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की निगरानी के उद्देश्य से 'दिव्यम' ऐप लॉच किया। इस ऐप से सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर, उप-मण्डलाधिकारी बल्ह स्मृतिका नेगी और जिला कल्याण अधिकारी मंडी समीर को उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। इन अधिकारियों ने कर्नाटक की सकमा और पश्चिम बंगाल की पद्मा मुर्मू को उनके परिवारों से मिलाने में सराहनीय भूमिका निभाई।

इस अवसर पर मंत्रमुग्ध करने वाली देव-ध्वनि भी प्रस्तुत की गई।

द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्र में 9 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू न जिला मंडी के द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 46.82 करोड़ रुपये लागत की 9

विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए 'अपना पुस्तकालय' कार्यक्रम के तहत नेरचौक और पधर में एक-एक पुस्तकालय का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 5.28 करोड़ रुपये की लागत से सब मार्केट यार्ड, टकोली के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण कार्य, मंडी-कमांद-कटौला-बजौरा सड़क पर कमांद में उहल नदी पर 12.44 करोड़ रुपये लागत से निर्मित पुल का उद्घाटन किया।

उन्होंने क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला मंडी में 1.33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित डीएनए ब्लॉक का लोकार्पण किया। उन्होंने मंडी से बीर-लाग तथा बाड़ी-गुमाणु सड़क पर 2.08 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित गरूड़ नाला एवं गणपति नाला डबल लेन पुल तथा रंधाड़ा से अलाथु वाया चचोला सड़क पर 3.15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल और मंडी में 3.82 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित खंड विकास कार्यालय भवन का उद्घाटन भी किया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विश्वकर्मा मंदिर मंडी के पास 1.55 करोड़ रुपये की लागत से भू-स्खलन शमन कार्यों, वल्लभ राजकीय डिग्री कॉलेज मंडी के विभिन्न खंडों में 12 करोड़ रुपये की लागत से भूकंप रेट्रोफिटिंग के कार्य तथा 5.18 करोड़ रुपये की लागत के सिक्कन मठ से कसान वाया मोरेगालू सड़क का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने 'मेरे शहर के 100 रत्न' कार्यक्रम का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मेरे शहर के 100 रत्न' कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में 6,800 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग

प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत क्रैक एकेडमी अनुमानित 34 करोड़ रुपये के निवेश से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 मेधावी विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करेगी।

निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा छः और उससे ऊपर के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से शीर्ष 100 विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग दी जाएगी, जबकि अगले 200 विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत तथा उसके बाद के 500 विद्यार्थियों को कोचिंग पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। कंपनी इन बच्चों को तब तक सहायता प्रदान करेगी, जब तक वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते।

राज्य सरकार इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए क्रैक एकेडमी को पूरा सहयोग देगी। एकेडमी जहां टेस्ट पेपर तैयार करेगी, वहीं शिक्षा विभाग परीक्षाओं के संचालन की देखरेख करेगा।

विद्यार्थियों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक मेगा जागरूकता अभियान भी शुरू किया। इस कार्यक्रम की पहल कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में की गई थी, जिसमें 50 स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था और वर्तमान में ज्वालामुखी के 220 चयनित विद्यार्थी इस योजना के तहत योग्यता आधारित कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। क्रैक एकेडमी की योजना 90 से अधिक कोचिंग सेंटर स्थापित करने की है, जिससे अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन के साथ 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

एकेडमी शिमला के रिज स्थित पुस्कालय के जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए 1.5 करोड़ रुपये का निवेश भी करेगी। मुख्यमंत्री ने एकेडमी को भवन के विरासत को संरक्षित रखते हुए विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से इसे आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने के निर्देश दिए।

विश्व शीतकालीन खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा: मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इटली के टयूरिन में 7 से 16 मार्च, 2025 तक आयोजित किए जा रहे विशेष ओलंपिक विश्व

शीतकालीन खेलों के लिए चयनित प्रदेश के विशेष एथलीटों और प्रशिक्षकों को शिमला से रवाना किया और उन्हें शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है कि इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए चयनित 49 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल में से 24 एथलीट और कोच हिमाचल प्रदेश से सम्बंधित हैं। उन्होंने कहा कि ये एथलीट स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, स्नोशूइंग और फ्लोर बॉल जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी प्रतिभागी इस आयोजन में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तथा देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी। युवाओं में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सरकार के इस प्रयास का उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों के प्रति उत्साहवर्धन करना है ताकि वे नशे की बुराई से बच सकें।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई है। रजत पदक विजेताओं के लिए 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है।

एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की गई है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई है। इस अवसर पर शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा भी उपस्थित थे।

मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक तकनीक अपनाने पर बल:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से प्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष डॉ. बलवीर वर्मा और महासचिव डॉ. पीयूष कपिला के नेतृत्व में ओक ओवर में भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक तकनीक अपनाने पर बल दिया और कहा कि राज्य सरकार इन संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग को सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतरीन चिकित्सा उपकरण स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीजों को गुणात्तमक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दृढसंकल्प है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शिमला कैंसर अस्पताल में रोगी देखभाल सुविधाओं को बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की और अधिकारियों को आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन मशीन स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में कैंसर उपचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां कैंसर रोगियों की देखभाल के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में पैट स्कैन मशीन और लिनैक मशीन भी स्थापित होगी। लिनैक मशीन का उपयोग लक्षित कैंसर उपचार के लिए किया जाता है और इसके दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज कैंडर के विलय के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाएगी।

सत्य कभी भी किसी न्यायपूर्ण कारण को नुकसान नहीं पहुंचाता

..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

ट्रंप के खुलासे पर मोदी की चुप्पी के मायने

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे से भारत की राजनीति में एक भूचाल की स्थिति पैदा हो गयी है। क्योंकि ट्रंप के ब्यानों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा और आर.एस.एस. सभी सवालों के घेरे में आ गये हैं। क्योंकि अमेरिका द्वारा यू.एस.एड के नाम पर भारत को इक्कीस मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता चुनावों में वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिये दी जा रही थी। ट्रंप ने नाम लेकर कहा है कि यह सहायता उनके दोस्त नरेन्द्र मोदी को दी गयी है। यदि ट्रंप का यह ब्यान सही है तो यह माना जायेगा कि अमेरिका इस सहायता के नाम पर भारत की चुनावी राजनीति में दखल दे रहा था। भारत में ई.वी.एम. की विश्वसनीयता पर लम्बे समय से सवाल उठते आ रहे हैं। इस बार तो वोटर टर्न आउट पर भी सवाल उठे हैं। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त सवालों के घेरे में चल रहे हैं। मामला अदालत जा पहुंचा है। इसलिये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिये अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता देना एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। विपक्ष बराबर सवाल पूछ रहा है कि इस सहायता को कैसे इस्तेमाल किया गया है। किन संस्थानों और व्यक्तियों को इस कार्य पर लगाया गया? आर.एस.एस. के भारत में पंजीकृत न होने को लेकर आर.टी.आई. के माध्यम से विवाद खड़ा हो गया है। संघ पर इसलिये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी 1993 तक अमेरिका के तेईस राज्यों का भ्रमण कर चुके थे और लीडरशिप ट्रेनिंग वहां से ले चुके थे जब वह एक साधारण स्वयं सेवक थे। मोदी, भाजपा और संघ पर उठते सवाल हर दिन गंभीर होते जा रहे हैं। सारे सवाल मोदी दोस्त ट्रंप के ब्यानों से उठे हैं। ट्रंप सच बोल रहे हैं या भारत मोदी, भाजपा और संघ को प्रश्नित करने के लिये कर रहे इस पर से पर्दा मोदी और संघ, भाजपा की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं से ही उठ सकता है। लेकिन इनकी चुप्पी इसको लगातार गंभीर बनाती जा रही है।

ट्रंप के खुलासे के बाद अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों का हथकड़ियां और बेडियो में जकड़ कर वापस भेजा जाना एक राष्ट्रीय शर्म बन गयी है। भारत इस पर अपनी कोई कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज नहीं करवा पाया है। उल्टे मोदी के मंत्रियों एस.जय शंकर और मनोहर लाल खट्टर के ब्यानों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। ट्रंप ने अमेरिकी सहायता को बन्द किये जाने का तर्क यह दिया है कि भारत टैरिफ के माध्यम से बहुत ज्यादा कमाई कर रहा है इसलिये उसे सहायता नहीं दी जानी चाहिये। ट्रंप के इस फैसले और अदाणी प्रकरण के कारण भारत के शेयर बाजार में निराशाजनक मन्दी शुरू हो गयी है। विदेशी निवेशकों ने अपनी पूंजी निकालना शुरू कर दी है। लेकिन इस सब पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार की चुप्पी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

ट्रंप के ब्यानों का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोई जवाब न दिया जाना अपने में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। मोदी की यह चुप्पी भाजपा और संघ पर भी भारी पड़ेगी यह तय है। इससे आने वाले समय में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस संभावित नुकसान से बचने के लिये देश में मोदी और भाजपा का कोई राजनीतिक विकल्प ही शेष न बचे इस दिशा में कुछ घटने की संभावनाएं हैं। इस समय भाजपा का विकल्प कांग्रेस और मोदी का विकल्प राहुल गांधी बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को कमजोर सिद्ध करने के लिये उसकी राज्य सरकारों को अस्थिर करने की रणनीति पर काम करना आसान है। क्योंकि आज कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग संघ, भाजपा और मोदी समर्थकों का मौजूद है। यदि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस के भीतर बैठे भाजपा के संपर्कों को बाहर नहीं निकाल पाता है तो कांग्रेस अपने ही लोगों के कारण राष्ट्रीय विकल्प बनने से बाहर हो जायेगी और यह स्थिति देश के लिये घातक होगी। क्योंकि मोदी और भाजपा तो ट्रंप के आगे पहले ही जुबान बन्द करके बैठ गये हैं। यदि समय रहते इस स्थिति को न संभाला गया तो देश आर्थिक गुलामी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पायेगा।

हिमाचल प्रदेश उच्च गुणवत्ता वाले रेनबो ट्राउट के आंख वाले अंडों के निर्यात में अग्रणी

हिमाचल प्रदेश ने उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को आपूर्ति करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली रेनबो ट्राउट के आंख वाले अंडों के अग्रणी निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर प्रगतिशील ट्राउट हैचरी मछली पालकों ने केवल उत्तराखंड को 9.05 लाख रेनबो ट्राउट के आंख वाले अंडे उपलब्ध करवाए हैं।

इस वर्ष मत्स्य विभाग ने कुल्लू जिले के पतलीकूहल और हामनी, मंडी जिले के बरोट, शिमला जिले के धमवाड़ी, किन्नौर जिले के सांगला और चंबा जिले के थल्ला, होली और भंडाल में स्थित अपने आठ सरकारी फार्मों से 12.60 लाख रेनबो ट्राउट के आंख वाले अंडों और 1.74 लाख ब्राउन ट्राउट के आंख वाले अंडों का उत्पादन किया है। इस प्रजाति की मछली का प्रजनन अभी भी जारी है, इसलिए आंख वाले अंडों का कुल उत्पादन 20 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, जो सरकारी क्षेत्र में पिछले साल के 15.79 लाख से उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र से भी बराबर मात्रा में योगदान की उम्मीद है, जिसमें कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में 9 कार्यात्मक हैचरी का सामूहिक रूप से 20 लाख आंख वाले अंडों के उत्पादन का लक्ष्य है। राज्य में कुल ट्राउट उत्पादन, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,402 मीट्रिक टन था, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,600 मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। विभाग ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को आंख वाले अंडों की आपूर्ति करने में कुल्लू के मछलीपालकों की सहायता की है। मंडी जिले के गांव स्वाद के शेर सिंह और मंडी जिले के जोगिंदर नगर क्षेत्र के गांव शानन के राजीव जसवाल और कुल्लू जिले के गांव फोजल की सरला नेगी जैसे प्रगतिशील मछलीपालकों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

राज्य के ठंडे पानी वाले क्षेत्रों में रेनबो ट्राउट उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के तहत मत्स्य विभाग ने कुल्लू के पतलीकुहल में ट्राउट फार्म में एक ठंडे पानी की रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम इकाई स्थापित की है। निजी क्षेत्र में भी इसी तरह की एक इकाई स्थापित की गई है और यह दोनों इकाइयां क्रियाशील हैं। मत्स्य विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने कहा कि सरकार की इन पहलों से राज्य में ठंडे पानी की जलीय कृषि में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। आने वाले सप्ताह में, जिला कुल्लू की सरला नेगी द्वारा अतिरिक्त 3 लाख रेनबो ट्राउट फाई भेजी जाएंगी, जिससे उत्तराखंड में जलीय कृषि और सुदृढ़ होगी।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच यह सहयोगात्मक प्रयास इस क्षेत्र में क्रांति लाएगा, जिससे स्थायी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। रेनबो ट्राउट के अलावा, राज्य में ब्राउन ट्राउट के बीज उत्पादन में भी वृद्धि देखी गई है। धीमी गति से बढ़ने वाली प्रजाति ब्राउन ट्राउट का उत्पादन मुख्य रूप से जैव विविधता के संरक्षण और मत्स्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जिला मंडी के बरोट और जिला शिमला के धमवाड़ी ट्राउट फार्मो में ब्राउन ट्राउट की नार्वे और डेनिश प्रजातियों का प्रजनन सफलतापूर्वक किया गया है। इन फार्मों में उत्पादित ब्राउन ट्राउट फिंगरलिंग को राज्य भर में ट्राउट-अनुकूल नदियों में स्थानांतरित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2024 तक 3,524 लोग मत्स्य पर्यटन की ओर आकर्षित होकर प्रदेश में आए जिससे हिमाचल की प्रमुख मत्स्य गंतव्य के रूप में पहचान स्थापित हुई है। ये उपलब्धियां जल, कृषि और मत्स्य पालन विकास को बढ़ावा देने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिससे राज्य रेनबो ट्राउट को आंख वाले अंडों के उत्पादन और सतत मत्स्य पालन में अग्रणी है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मत्स्य पालन विभाग की पहलों ने न केवल जलकृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है, बल्कि राज्य के युवाओं को इस क्षेत्र में नए अवसरों को तलाशने के लिए प्रेरित भी किया है। सतत और वैज्ञानिक जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देकर, हम किसानों की अगली पीढ़ी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बना रहे हैं।

नदी नालों में अवैध खनन धार्मिक दृष्टि से अपराध

अवैध खनन के खिलाफ जिला चंबा में वर्ष 2024 में 860 चालान कर वसूला 30 लाख 08 हजार 950 रुपए जुर्माना

जिला चंबा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस तथा खनन विभाग द्वारा निरंतर सख्त कार्यवाही अमल में लायी जा रही है तथा भविष्य में भी इसकी रोकथाम के लिए पुलिस व प्रशासन पूर्णत: सतर्क है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि जिला में अवैध खनन की रोकथाम के लिए पुलिस तथा खनन विभाग निरंतर कड़े कदम उठा रहे हैं इस कड़ी में वर्ष 2024 के दौरान जिला चंबा अवैध खनन से संबंधित मामलों में 860 चालान किए गए तथा 30 लाख 08 हजार 950 रुपए जुर्माना बसूला गया।

इसमें से पुलिस विभाग चंबा द्वारा 703 चालान कर 21 लाख 67 हजार 150 रूपए जुर्माना वसूला गया है जबकि खनन विभाग द्वारा 74 चालान कर 8 लाख 41 हजार 800 रूपए जुर्माना बसूला गया है। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा की गई कारवाई में चंबा उप मंडल में 238 चालान कर 1132850 रूपए, डलहौजी उपमंडल में 135 चालान कर 345900 रूपए, सलूनी उपमंडल में 196 चालान कर 470900 रूपए तथा पांगी व भरमौर उपमंडलों में 134 चालान कर 217500 जुर्माना राशि वसूल की गई है।

यही नहीं अवैध खनन के रोकथाम की निरंतरता को जारी रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2025 के दौरान अब तक कुल 92 चालान कर 3 लाख 700 रूपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई, इनमें चंबा उपमंडल में 32 चालान कर 115300 रूपए, डलहौजी उपमंडल में 26 चालान कर 108700 रूपए, सलूनी उपमंडल में 33 चालान कर 75700 रूपए तथा पांगी व भरमौर उपमंडलों में 1 चालान कर 1000 जुर्माना राशि वसूल की गई है।

उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ भविष्य में भी जिला में निरंतर सख्त कारवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन न केवल पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है बल्कि कानूनी दृष्टि से भी दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि जिला चंबा की रावी सहित अन्य नदियां धार्मिक आस्था का प्रतीक है, इसलिए नदी नालों में अवैध खनन धार्मिक दृष्टि से भी अपराध है। उन्होंने जिला चंबा के समस्त जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों तथा आम जनमानस से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में अवैध खनन पाये जाने पर पुलिस व प्रशासन को सूचित करें ताकि बिगड़ते पर्यावरण की प्रमुख वजह अवैध खनन पर पूरी तरह विराम लगाया जा सके।

न्याय का डिजिटल परिवर्तनः भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में एआई को एकीकृत करने की प्रक्रिया

'प्रौद्योगिकी पुलिस, फोरेंसिक, जेल और न्यायालयों को एकीकृत करेगी और उनके काम की गति में भी वृद्धि करेगी। हम एक ऐसी न्याय प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, जो पूरी तरह से भविष्य के लिए तैयार होगी।' – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

परिचय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जिससे दक्षता, पहुंच और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो रही है। न्यायिक प्रक्रियाओं, वाद प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान और कानून प्रवर्तन में एआई को एकीकृत करके, भारत संचालन-प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहा है, देरी में कमी ला रहा है और न्याय को सभी के लिए अधिक सुलभ बना रहा है।

न्यायपालिका को लंबित मामलों, भाषा संबंधी बाधाओं और डिजिटल

आधुनिकीकरण की आवश्यकता जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मशीन लर्निंग (एमएल), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी), ऑप्टिकल व्यक्तित्व पहचान (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर) और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण (प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स) सहित एआई-संचालित तकनीकों का उपयोग, अब प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करने, वाद निगरानी में सुधार करने और अपराध की रोकथाम को सशक्त करने के लिए किया जा रहा है।

ई-कोर्ट परियोजना चरण III, एआई की सहायता से कानूनी अनुवाद, पूर्वानुमानात्मक पुलिस कार्य और एआई-संचालित कानूनी चैटबॉट जैसी पहल कानूनी परिदृश्य को नया रूप दे रही हैं, जिससे प्रक्रियाएं तेज़, स्मार्ट और अधिक पारदर्शी हो रही हैं। हालांकि, एआई को अपनाने में विशेष रूप से डेटा सुरक्षा, नैतिक शासन और कानूनी अनुकूलन से जुड़ी चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन भारत की न्याय प्रणाली को मजबूत करने की इसकी क्षमता अद्वितीय है।

यह लेख भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका विचार करता है और अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने में इसके अनुप्रयोगों, प्रभाव और भविष्य की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

ई-कोर्ट परियोजना में एआई (चरण III) – न्यायिक डिजिटल परिवर्तन में एक बड़ा कदम

सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में शुरू की गई ई-कोर्ट परियोजना, डिजिटल नवाचार के माध्यम से एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य न्यायिक कार्यों को आधुनिक बनाना है। चरण III में, परियोजना भारत में न्यायालयों में वाद प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समाधानों को एकीकृत करती है। यह चरण अधिक उत्तरदायी और प्रभावी न्यायिक प्रणाली प्रदान करने के पूर्ववर्ती डिजिटल परिवर्तन प्रयासों पर आधारित है।

ई-कोर्ट में प्रमुख एआई अनुप्रयोग

स्वचालित केस प्रबंधन

एआई - संचालित उपकरण अब स्मार्ट सूची-निर्माण, केस प्राथमिकता और लंबित मामलों में सक्रिय रूप से कमी लाने के लिए उपयोग किये जा रहे हैं। ये प्रणालियां संभावित देरी और

स्थगन का पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण का उपयोग करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय पर वाद समाधान के लिए न्यायिक संसाधनों को इष्टतम रूप से आवंटित किया जा रहा है।

कानूनी अनुसंधान और दस्तावेज तैयार करने में एआई

उन्नत एआई-संचालित उपकरण कानूनी अनुसंधान को सुव्यवस्थित करके, प्रासंगिक वाद उदाहरणों की पहचान करके और निर्णयों का सारांश तैयार करके न्यायाधीशों और वकीलों की सहायता करते हैं। यह तकनीक न केवल अनुसंधान प्रक्रिया को गति प्रदान करती है, बल्कि कानूनी दस्तावेज़ निर्माण की गुणवत्ता और निरंतरता को भी बढ़ाती है।

एआई की सहायता से दाखिल करना और न्यायालय प्रक्रियाएं

ऑप्टिकल व्यक्तित्व पहचान (ओसीआर) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) का एकीकरण दस्तावेज़ डिजिटलीकरण में क्रांति ला रहा है। ये प्रौद्योगिकियाँ न्यायालय के दस्तावेज़ों को दाखिल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करती हैं, जिससे तेज़ प्रक्रिया सुनिश्चित होती है और दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया में त्रुटियाँ कम होती हैं।

उपयोगकर्ता सहायता और चैटबॉट के लिए एआई

एआई-संचालित वर्चुअल कानूनी सहायक और चैटबॉट, वादियों को वाद की वास्तविक समय पर स्थिति, प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन और आवश्यक कानूनी अपडेट के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। चौबीसों घंटे उपलब्ध यह डिजिटल सहायता खासकर कानूनी प्रक्रियाओं से अपरिचित व्यद्रियों के लिए न्यायिक प्रणाली को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाती है।

वाद परिणामों में पूर्वानुमानित विश्लेषण के लिए एआई

एआई मॉडल, संभावित वाद परिणामों और जोखिम आकलन में पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक निर्णयों और वाद डेटा का विश्लेषण करते हैं। यह क्षमता न्यायिक अधिकारियों को जानकारी आधारित निर्णय लेने और प्रभावी वाद रणनीतियां विकसित करने में मदद करती है, जिससे सक्रिय न्यायिक व्यवस्था में योगदान मिलता है।

बजट और कार्यान्वयन

भारत सरकार ने ई-कोर्ट चरण III परियोजना के लिए कुल 7210 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो न्यायिक डिजिटल परिवर्तन के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। इस बजट में, भारत के उच्च न्यायालयों में एआई और ब्लॉकचेन तकनीकों के एकीकरण के लिए विशेष रूप से 53.57 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह वित्तीय प्रतिबद्धता न्यायिक प्रणाली में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीक का लाभ उठाने के महत्व को रेखांकित करती है।

कानूनी अनुवाद और भाषा पहुंच के लिए एआई

भारत की न्यायिक प्रणाली मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में कार्य करती है, जो गैर-अंग्रेजी बोलने वाले वादियों के लिए बाधाएं पैदा करती है। कानूनी दस्तावेजों और निर्णयों को सुलभ बनाने के लिए एआई-संचालित कानूनी अनुवाद उपकरण तैनात किए जा रहे हैं।

एआई – सहायता प्राप्त कानूनी अनुवाद का विस्तार

कानून प्रवर्तन और अपराध रोकथाम में एआई

अपराध का पता लगाने, निगरानी करने और आपराधिक जांच को बढ़ाने के लिए एआई को पुलिस कार्य और कानून प्रवर्तन में एकीकृत किया जा रहा है।

कानून प्रवर्तन में प्रमुख एआई अनुप्रयोग

पूर्वानुमानित पुलिस कार्य

एआई मॉडल अपराध पैटर्न, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और आपराधिक व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन को सक्रिय उपाय करने में मदद मिलती है।

निगरानी और जांच के लिए एआई

अपराध स्थल की निगरानी और संदिग्ध निगरानी के लिए स्वचालित ड्रोन।

चेहरे की पहचान प्रणाली को राष्ट्रीय आपराधिक डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया।

साक्ष्य और डिजिटल अपराध सिलसिले (ट्रेल्स) की जांच करने के लिए एआई-संचालित फोरेंसिक विश्लेषण।

एफआईआर दर्ज करने और न्यायिक कार्यवाही में एआई

एआई-संचालित स्पीच-टू-टेक्स्ट टूल वास्तविक समय में एफआईआर दर्ज करने और वाद दस्तावेज तैयार करने में सहायता करते हैं।

एआई गवाह की गवाही के विश्लेषण और न्यायालय कक्ष साक्ष्य मूल्यांकन में सुधार कर रहा है।

डेटा-संचालित अपराध की निगरानी और खुफिया प्रणाली

एआई से अपराध और आपराधिक निगरानी नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) का विस्तार होता है।

ई-जेल और ई-फोरेंसिक डेटाबेस के साथ एकीकरण।

एआई और 5जी: कानून प्रवर्तन के लिए विमर्श 2023 हैकथॉन

दूरसंचार विभाग (डॉट) और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी), गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित विमर्श 2023 5जी हैकथॉन में अपराध की रोकथाम के लिए एआई-संचालित नवाचारों की खोज की गई।

विमर्श 2023 में प्रदर्शित नवाचार

आवाज पहचान का उपयोग करके एआई-सहायता प्राप्त एफआईआर दर्ज करना।

ड्रोन-आधारित अपराध निगरानी और संदिग्ध निगरानी।

अपराध स्थल जांच के लिए संवर्धित वास्तविकता (ए आर) अनुप्रयोग।

राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस कार्य के लिए एआई-संचालित पूर्वानुमानित विश्लेषण।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वाद प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, अपराध की रोकथाम और भाषा की सुलभता को बढ़ाकर भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में बदलाव ला रही है। एआई-संचालित उपकरण जैसे पूर्वानुमानित विश्लेषण, स्वचालित दस्तावेज़ीकरण, चैटबॉट और स्मार्ट पुलिस सिस्टम, कानूनी प्रणाली की दक्षता और प्रशासन में सुधार कर रहे हैं। हालांकि, जिम्मेदारी से एआई अपनाने के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा, कानूनी सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता है, ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं में मानवीय निर्णय को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसका समर्थन करना सुनिश्चित हो सके। एआई-संचालित कानूनी अनुसंधान, ब्लॉकचेन-सुरक्षित वाद रिकॉर्ड, एआई विश्लेषण के माध्यम से न्यायिक पारदर्शिता तथा कानून प्रवर्तन में बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा के आधार पर कानून और न्याय में एआई का भविष्य निर्धारित होगा।

निरंतर सरकारी निवेश और नियामक निगरानी के साथ, एआई में भारत की न्याय प्रणाली को सभी नागरिकों के लिए तेज़, अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की क्षमता है।

पीएम मोदी की योजनाओं से प्रदेश का जनमानस लाभान्वित:बिंदल

शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि नरेन्द्र भाई मोदी की अनेक-अनेक योजनाओं से हिमाचल प्रदेश का जनमानस लाभान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा दी गई किसान-सम्मान निधि की 19वीं किश्त देश के किसानो-बागवानो के लिए अमृत की तरह से कार्य कर रही है। गत दिन नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के 9 करोड़ 63 लाख किसानो-बागवानो के खाते में 19वीं किश्त डाली गई और किसान-सम्मान निधि के 6 वर्ष पूर्ण होकर सातवां वर्ष प्रारंभ हुआ।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 9 लाख 73 हजार किसान-बागवान किसान-सम्मान निधि को प्राप्त कर रहे हैं जिससे गरीब किसानो को अनेक प्रकार की सहायता पहुंच रही है। उन्होनें कहा कि किसानो को मिलने वाली युरिया खाद लगभग 300 रूपये प्रति बोरी के दाम पर उपलब्ध करवाई जा रही है जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खाद का दाम 3000 रूपये प्रति बोरी है अर्थात 2700 रू0 प्रति बोरी की सबसिडी देते हुए 2 लाख करोड़ रू0 की सबसिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस प्रकार किसान-बागवान व ग्रामीण कल्याण के हित में मोदी सरकार कार्य कर रही है।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि गांवो को सड़कों से जोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हिमाचल से ही किया गया था और वर्तमान में 40 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों में से लगभग 20 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़के पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ही बनाई गई है।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के रहते हुए भी हिमाचल को 2700 करोड़ रू0 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-3 के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जा चुका है और पीएमजीएसवाई-4 के अंतर्गत भी लगभग 500 करोड़ रू0 हिमाचल को प्राप्त होगा। इसी प्रकार मनरेगा के माध्यम से सर्वाधिक धनराशि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास पर व्यय की जा रही है और पंचायतों को मिलने वाली समस्त राशियां सीधा-सीधा पंचायतों के खाते में केन्द्र से पहुंच रही है।

डॉ. बिन्दल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा महाकुम्भ में सपरिवार डुबकी लगाने की खबर पर चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि देर आए, दुरूस्त आए। 2022 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बयानात दिए कि 97 प्रतिशत हिन्दु आबादी वाले प्रदेश में हिन्दुवादी विचारधारा को हराकर वे मुख्यमंत्री बने हैं। इस प्रकार हिन्दुत्व की विचारधारा पर जोरदार प्रहार करने वाले सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रयागराज में डुबकी लगाई।

डॉ. बिन्दल ने सवाल खड़ा किया कि ये डुबकी मोदी जी व योगी जी की प्रेरणा से लगाई या फिर विक्रमादित्य और मुकेश अग्निहोत्री के डुबकी लगाने के बाद मुख्यमंत्री ने कम्पीटीशन में डुबकी लगाई, यह सवाल तो खड़ा होता ही है।

जोश में नहीं होश में गाड़ी चलाएं:उपमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। परिवहन विभाग द्वारा जिला प्रशासन मंडी के सहयोग से अन्तराष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रोड सेफटी जागरूकता रैली निकाली गई। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने

इस रैली को सेरी मंच से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रैली सेरी मंच से मंगवाई, चक्कर, नेरचौक होते हुए डडौर में जाकर संपन्न हुई। रैली में 100 बाइक और 25 कारें शामिल रही। रैली में उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने भी भाग लिया। वह वाईक पर सवार थे। रैली में शामिल वाईकर और चौपहिया वाहन चालक पूरी सेफ्टी के साथ निर्धारित गति में वाहन चला रहे थे।

उपमुख्यमंत्री रैली को हरी झंडी दिखाने के उपरांत अपने संदेश में कहा कि जोश में नहीं होश में गाड़ी चलाएं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को लगातार जागरूकता किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से गाड़ी चलाते समय जीवन पर्यन्त यातायात नियमों और कानूनों का अक्षरस: पालन करने, मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाने, तेज गति से वाहन न चलाने, वाहन का रखरखाव व नियमित जांच करवाने, उच्च मार्गो में अपनी लेन में चलने, सदैव सीट बैल्ट व दोपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग न करने, रात्रि में लो बीम का प्रयोग करने, नींद, थकान और तनावग्रस्त होने पर वाहन न चलाने, वाहनों में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को न बिठाने का आहवान किया।

इस अवसर पर एचआरटीसी की बीओडी के निदेशक धमेंद्र धामी, जगदीश रेड्डी, एसपी साक्षी वर्मा, एडीएम डॉ मदन कुमार, आरटीओ गिरीश समरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

विकसित भारत निर्माण में डिजिटल इंडिया व यूपीआई की भूमिका अहम: अनुराग सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मोदी जी के वर्ष 2027 तक विकसित भारत

निर्माण में डिजिटल इंडिया व यूपीआई की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत को वर्ष 2047 विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सभी भारतवासी अपनी क्षमता के अनुरूप सहयोग दे रहे हैं। आज तकनीकी के दौर में बहुत कम लोग होंगे जो डिजिटल इंडिया और यूपीआई से अछूते होंगे और विकसित भारत निर्माण में डिजिटल इंडिया और यूपीआई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से की गई थी। डिजिटल इंडिया सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों के विस्तार के माध्यम से सभी नागरिकों के जीवन में सुधार कर रहा है। कांग्रेसी नेता एक समय यूपीआई और डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते थे आज अब वही डिजिटल इंडिया आम आदमी की ताकत बन चुकी है। आज फल सब्ज़ी विक्रेता तक यूपीआइ से लेनदेन कर रहे हैं। कांग्रेसी भारत की जनता की क्षमता पर संदेह करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। खुलेआम कहा जाता था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मोदी सरकार का देश के सामान्य मानविकी समझ पर भरोसा था। मोदी सरकार ने खुद आगे बढ़कर डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता आसान बनाया हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी, फिर लोकल कलाकार, या कारीगर हों, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है। डिजिटल इंडिया ने सभी कार्य सुलभ बनाया है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विज़न है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी परिदृश्य में हो रहे बदलावों का सामाजिक स्तर पर गहरा असर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिनटेक को बढ़ावा देने की नीति की बदौलत यूपीआई अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच रहा है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वित्तीय सेवाओं की खाई को पाट रहा है। मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया यूपीआई वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म बन गया है। जनवरी महीने में पहली बार यूपीआई ट्रांजैक्शन 16.99 बिलियन से अधिक हुआ और मूल्य 23.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो किसी भी महीने में दर्ज की गई सबसे बड़ी संख्या है। यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की आधारशिला बना हुआ है, जो देश भर में खुदरा भुगतानों में 80 प्रतिशत का योगदान देता है। जनवरी तक 80 से अधिक यूपीआई ऐप बैंक ऐप और थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर और 641 बैंक वर्तमान में यूपीआई इकोसिस्टम पर लाइव हैं। UPI पूरी दुनिया के लिए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण का साधन बने, इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। मेरा सुझाव है कि हमारे वित्तीय संस्थानों को भी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए फिनटेक के साथ अधिक से अधिक भागीदारी करनी चाहिए।

उप-मुख्यमंत्री ने डेरा बाबा रुद्रानंद के संस्थापक के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने डेरा बाबा रुद्रानंद के संस्थापक वेदांताचार्य 1008 स्वामी श्री श्री सुग्रीवानंद महाराज जी के निधन पर गहरा शोक व्यद्र किया है। उन्होंने कहा कि महाराज जी का स्वर्गवास पूरे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि महाराज जी द्वारा दी गई शिक्षाएं हमेशा हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी।

उप-मुख्यमंत्रे ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है।

प्रदेश में भरे जाएंगे टीजीटी के 937 और जेबीटी के 1762 पद

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से सीधी भर्ती के आधार पर टीजीटी कला, मेडिकल और नॉन-मेडिकल के 937 पदों को भरने के लिए आग्रह किया है। ये पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने जेबीटी जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापकों के 1295 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने के लिए आग्रह किया है। इसके अलावा, आयोग को 467 पदों को भरने के लिए भी आग्रह किया गया है जो पूर्व सरकार द्वारा सृजित किए गए थे लेकिन भरे नहीं गए थे। राज्य सरकार द्वारा जेबीटी के कुल 1762 पदों को भरने का आग्रह किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों को बैचवाइज आधार पर पहले ही भर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने को सर्वोच्च अधिमान दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सभी शैक्षणिक संस्थानों में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोल रही है, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी, ताकि छात्र आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के छात्रों में सीखने का स्तर सबसे अधिक है तथा शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक समय की मांग के अनुसार सुधार किए जा रहे हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा हमेशा से इस पहाड़ी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान में राज्य की साक्षरता दर 83 प्रतिशत से भी अधिक है जबकि वर्ष 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के समय हमारी साक्षरता दर मात्र 7 प्रतिशत थी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और हाल ही में जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने कुल राज्य बजट का लगभग 20 प्रतिशत अकेले शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया है, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

भ्रष्टाचार मामलों में हिमाचल के हालात दिल्ली जैसे:डॉ.सहगल

शिमला। भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं पूर्व सरकार में मंत्री डॉ राजीव सहजल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल के समय शराब नीति बदलने से दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। राजीव ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद शराब नीति बदलने के कारण 2 हजार 900 करोड़ रुपये के नुकसान की बात सामने आयी है। आम आदमी पार्टी की 10 साल तक दिल्ली में सरकार रही, लेकिन उन्होंने एक बार भी सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं किया, यह हैरानी की बात है। सीएजी रिपोर्ट में मुख्यतौर पर 4 हजार 400 करोड़ रुपये के घोटाले का पता चला है। सीएजी ने भी माना है कि 4 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। केजरीवाल अपने दोस्तों को शराब कारोबार का काम दिया। दिल्ली में पहले 101 लोग शराब का कारोबार करते थे, लेकिन अब 12 लोगों तक ही इसे सीमित कर दिया गया, इसमें तीन लोगों के पास 71 फीसदी शराब कारोबार की जिम्मेदारी थी। बाद में वो तीनों केजरीवाल के साथ जेल भी गये। उन्होंने अपने दोस्तों को शराब का काम देने के लिए शराब नीति में बदलाव किया था।

उन्होंने कहा कि लाइसेंसधारियों ने 28 दिसंबर, 2021 से 4 जनवरी, 2022 तक कोविड प्रतिबंध का हवाला देते हुए उत्पाद शुल्क से छूट की मांग की। विभागों ने कहा, छूट पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि निविदा दस्तावेज में इसका प्रावधान नहीं था। प्रभारी मंत्री आप नेता सिसोदिया ने विभागीय फैसले को खारिज कर दिया और 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 के दौरान बन्द दुकानों के लिए छूट देने को मंजूरी दे दी। इससे स्पष्ट होता है कि आप ने पूर्ण भ्रष्टाचार किया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी हालात कुछ दिल्ली भ्रष्टाचार मामलों जैसे है, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले हिमाचल में जनता के समक्ष आ रहे है। प्रदेश की जनता हिमाचल में कांग्रेस राज से परेशान है, हिमाचल ऑन सेल की व्यापक चर्चा प्रदेश की जनता में अभी भी बनी हुई है। हिमाचल के सरकारी होटल से लेकर सरकारी संस्थानों को लगातार बेचना का प्रयास किया जा रहा है।

नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स अधिसूचित की जाएगी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगामी छः माह में

मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत पाए गए हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पीआईटी-एनडीपीएस स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम को अक्षरशः लागू करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि पीआईटी-एनडीपीएस मामलों के निष्पादन में देरी क्यों हो रही है तथा उन्हें एक सप्ताह के भीतर सभी मामलों की समीक्षा कर उनका निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों और उनके सहयोगियों की संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस विभाग को संदिग्धों के बैंक खातों की जांच करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा नशा तस्करी व नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स भी अधिसूचित की जाएगी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने तथा राज्य से नशाखोरी को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं नियमित रूप से नशा विरोधी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे।

उन्होंने पुलिस विभाग को पंचायत स्तर तक नशा तस्करों तथा पीड़ितों की मैपिंग करने तथा 15 मार्च, 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों तथा नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नशा तस्करी में मामले दर्ज करने में आनाकानी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सभी एनडीपीएस मामलों का निष्कर्ष जानने तथा पूरे नशा नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए मामलों की फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने तथा पैरोल के प्रावधानों को सख्त बनाने के लिए दृढ़ता से प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश एंटी ड्रग एक्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें पीड़ितों तथा नशा तस्करों के बीच स्पष्ट अंतर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिरमौर जिला के कोटला बेहड़ में पीड़ितों के लिए अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र भी स्थापित कर रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने फार्मा कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए तथा कहा कि जो कंपनियां साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्त पाई जाएंगी, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी तथा उनके लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने पर भी बल दिया, ताकि लोगों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत तथा ओंकार चंद शर्मा, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, महानिदेशक सीआईडी एस.आर. ओझा, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव आशीष सिंघमार व राजेश शर्मा, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार जनता को पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। लंबे समय से विभिन्न विभागों में संवेदनशील पदों पर आसीन अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया एक बार पुनः शुरू हो गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग सहित कुछ अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और विभागों को इस प्रक्रिया के लिए तैयारी करने को कहा है।

सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को जवाबदेह और पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने उद्योग विभाग को खनन पटों की नीलामी प्रक्रिया में हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों के उपयोग के लिए नए नियम बनाएगी ताकि धन का उपयोग समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किया जा सके।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि दो वर्ष पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खनन से प्रदेश सरकार को 240 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार के दक्ष व व्यावहारिक प्रयासों से पिछले वित्त वर्ष में यह राजस्व बढ़कर 314 करोड़ रुपये हो गया तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 360 करोड़ रुपये तक होने की उम्मीद है। इस प्रकार केवल दो वर्षों में राजस्व में 120 करोड़ रुपये की वृद्धि होने जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है तथा पर्यटन, जल विद्युत, खाद्य प्रसंस्करण, डाटा भंडारण तथा डेयरी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। इन पहलों से न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने उद्योगों को सस्ती विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती विद्युत उपलब्ध है।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नज़ीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक उद्योग डॉ. यूनुस तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

देश में तीन हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए वन मंजूरी प्राप्त हुई

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में तीन हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से प्रथम चरण की मंजूरी स्टेज-वन क्लीयरेंस मिल गई है। इनमें चंबा जिले के होली और पांगी में हेलीपोर्ट के साथ-साथ कुल्लू जिले के मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर के पास एक हेलीपोर्ट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में हेलीपोर्ट के निर्माण में तेजी लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में कोई देरी न हो और सभी आवश्यक औपचारिकताएं, विशेष रूप से वन मंजूरी की प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण की जाए।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के उद्देश्य से हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए हेलीपोर्ट के विकास को विशेष प्राथमिकता दी है। बेहतर पर्यटन बुनियादी ढांचे से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हेलीपोर्ट परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। इस पहल से न केवल परिवहन सुविधाओं का विकास होगा बल्कि पर्यटन क्षेत्र और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों और जनजातीय क्षेत्रों में 16 हेलीपोर्ट बनाकर हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आगंतुकों के लिए सुविधाओं में सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अतिरिक्त, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार कार्य में तेजी लाई गई है और भुंतर हवाई अड्डे का विस्तार करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक प्रदेश में अपने पसंदीदा गंतव्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

सभी विभाग सीएम डैशबोर्ड के दायरे में लाए जाएंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित 8 विभागों के 66 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक केपीआई की प्रगति एवं प्रदर्शन की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया।

उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत ग्रामीण विकास के 8 केपीआई, लोक निर्माण विभाग के 8 केपीआई, जल शक्ति विभाग के 6 केपीआई, राजस्व के 7 केपीआई, महिला एवं बाल विकास के 4 केपीआई, शिक्षा विभाग के 10 केपीआई, जनजातीय विकास के 5 केपीआई तथा स्वास्थ्य विभाग के 18 केपीआई को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम विकास की गति को तेज करने तथा विभिन्न विभागों के लाभार्थियों की सटीक जानकारी एक मंच पर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने विभागों से लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सही निर्णय लेने के लिए सटीक आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करेंगे।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी

तथा डेटा एकत्रिकरण और विश्लेषण सुव्यवस्थित होगा। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों पर प्रशासनिक दबाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड में इन विभागों के 11 लाख से अधिक लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध है। उन्होंने काह कि सभी सरकारी विभागों को सीएम डैशबोर्ड के दायरे में लाया जाएगा तथा केपीआई की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एक बार यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बोर्ड और निगमों को भी इस प्लेटफॉर्म पर शामिल कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लाभार्थियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार ला रही है। आधुनिक तकनीक भविष्य की चुनौतियों से निपटने में महत्त्वपूर्ण साधन साबित हो सकती है। सरकार सुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विभागों को राज्य के लोगों को उनके घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए।

उन्होंने इस अवसर पर जिला सुशासन सूचकांक भी जारी किया।

उन्होंने आर्म्सडेल भवन चरण-3 के सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और रणजीत सिंह राणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत और ओंकार चंद शर्मा तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

निदेशालयों के पुनर्गठन से अध्यापकों की प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा असर

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रस्तावित निदेशालयों के पुनर्गठन से किसी भी अध्यापक के प्रमोशन अवसरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास कर रही है और इसी दिशा में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार गांवों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सफतापूर्वक सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है और उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन में विद्यार्थियों के साथ-साथ सभी शिक्षकों के हितों का ख्याल रखा जाएगा ताकि उनके हित किसी भी तरह से प्रभावित न हों। इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत सभी अध्यापक गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने में शिक्षा विभाग के लिए रीढ़ की हड्डी हैं और सभी के सहयोग से शिक्षा विभाग में सकारात्मक बदलाव संभव होगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कर्मचारी हितों में उठाए जाएंगे कड़े कदम:समीर रस्तोगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में कई वर्षो से रिक्त पड़े मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कमी पर गहरी चिंता जताते हुए हिमाचल प्रदेश वन बल मुखिया समीर रस्तोगी ने गहरी चिंता जताई है । उन्होंने बताया कि किसी भी विभाग में कर्मचारी अहम भूमिका निभाते हैं। कर्मचारियों की भारी कमी विभाग की कार्यकुशलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह बात वन बल मुखिया ने वन विभाग मुख्यायालय के सभागार में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताई। बैठक में हिमाचल प्रदेश से लगभग चार सौ से अधिक कर्मचारी ऑन लाईन और ऑफ़लाईन माध्यमों से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त वन विभाग मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल

ने वन विभाग में कर्मचारियों की अनेक मांगों को बैठक में रखा। वन विभाग में पिछले कई वर्षो से जे.ओ.ए.(आई.टी.) के एक बैच के कर्मचारियों की वेतन विसंगते को दूर करने के लिए एक कमेटी गठित कर उसे विभागीय स्तर पर तुरन्त सुलझाने के आदेश दिए। रस्तोगी ने कर्मचारी महासंघ की मांग पर हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कार्यालयों में दफ्तरों में बैठे फील्ड स्टाफ की सूची बना कर उन्हें फील्ड में भेजने की कर्मचारी महासंघ की मांग को जायज़ ठहराते हुये बताया कि फील्ड के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारयों को दफ्तरों में पोस्ट किया जाना विभाग के लिये सही नहीं है। वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने आंकड़े रखते हुए वन बल मुखिया को बताया कि हिमाचल प्रदेश में लगभग दो सौ से भी अधिक वन रक्षकों सहित डिप्टी रेंजर और रेज ऑफिसर के अनेक कर्मचारी अनावाश्यक तरीके से तैनात हैं । हिमाचल में लगभग दो सौ से अधिक बीटें रिक्त वन रक्षकों की कमी के कारण रिक्त पडी हैं और अनेक वन रक्षकों के पास पांच-पांच बीटों का चार्ज है, जिसके कारण फील्ड में कर्मठता से कार्य कर रहे वन रक्षकों, डिप्टी रेंजरों और रेंज अफसरों परअतिरिक्त कार्य का बोझ होने से मानसिक तनाव भी बढ़ा है। इसका उत्तर देते हुए वन बल मुखिया ने कड़े आदेश दिए कि हिमाचल प्रदेश में दफ्तरों में कार्य कर रहे फील्ड कर्मचारियों की सूचि तैयार की जाये और उन्हें फील्ड में भेजने के तुरन्त आदेश दिए जायें। हिमाचल प्रदेश में छोटे कर्मचारियों के सरकारी मकानों की जर्जर हालत पर चिंता जताते हुए वन बल मुखिया ने आदेश दिये कि छोटे कर्मचारियों के सरकारी मकानों में आवश्यक मुरम्मत को सुनिश्चित किया जाये। अधिकारियों के मकानों पर ज़रुरत से अधिक व्यय हो रहे धन पर चिंता जताते हुए वन बल मुखिया ने आदेश दिये कि भविष्य में मकानों की मुरम्मत को बराबरी से करने के लिए मुरम्मत पर बजट को आधा आधा बांटा जाये और सभी मकानों की बराबरी से मुरम्मत की जाये। वन बल मुखिया ने हिमाचल प्रदेश में मिनिस्ट्रियल स्टाफ में ट्रेनिंग बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग को जायज़ ठहराते हुए वन विभाग में नए कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान करने के लिए भी कड़े कदम उठाने की बात कही। हिमाचल प्रदेश में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग सौ से भी अधिक रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार के समक्ष रखने की बात भी कही। वन विभाग के सरकारी मकानों की हाऊस अलोटमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी महासंघ की मांग पर एक कमेटी गठित कर विभाग के विशेष नियम बनाने के आदेश देते हुए एक कमेटी गठित करने के आदेश दिए, जिसकी रिपोर्ट आगामी बीस दिनों के भीतर सौंपने के भी आदेश दिए। वन बल मुखिया ने प्राथमिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश वन विभाग में छोटे कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से नए मकान बनाने के लिए प्रपोज़ल सरकार को भेजने की मांग को जायज़ ठहराते हुए निर्देश दिए कि सबसे पहले शिमला में कुछ सरकारी मकान बनाए जाने के लिए बजट की मांग की जायेगी और शिमला में कुछ नए सरकारी मकान बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वन विभाग कर्मचारी महासंघ की अनेक मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर समीर रस्तोगी ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ के वर्ष 2025 के कैलेंडर का विमोचन भी किया । इस अवसर पर कर्मचारी महासंघ के अनेक पदाधिकारियों सहित विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर वन बल मुखिया को सम्मानित भी

केंद्र से हिमाचल को मिल रही है बड़ी मदद:कश्यप

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि यह नारसाचनक है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चौथी किस्त केंद्र से प्रदेश सरकार को आने वाली है और अभी तक कई कार्य ऐसे हैं जो की इस महत्वपूर्ण योजनाओं के चरण एक और दो के भी पूरे नहीं हुए है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर जो सरकार सत्ता में आयी लेकिन सवा दो साल का समय बीत गया प्रदेश में एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पायी, सारी फेल हो चुकी हैं। जो विकास कार्य प्रदेश में चले थे आज अवरुद्ध हैं, पूर्व सरकार के समय में जो काम शुरू किए गए थे आज वह भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं और निरन्तर विकास के मामले में हिमाचल प्रदेश पिछड़ता जा रहा है।

कश्यप ने कहा कि विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में बेहतर ढंग से कर सके केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिये भरपूर बजट हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है। केंद्र ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि जो पैसा केंद्र की योजनाओं का पहले ट्रेजरी में जाता था, अब सीधा योजनाओं के लिए आयेगा और सीधा योजना के ऊपर ही खर्च किया जायेगा। इससे भी योजनाओं को पूरा करने में निश्चित रूप से फायदा होगा।

हिमाचल प्रदेश तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 90:10 की रेशो में हिमाचल को रखा है और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद भी मिल रही है।

उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार झूठा रोना रो रही है, आप ने आम बजट भी देखा होगा कि बहुत सारी स्कीमें केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी है, हाल ही में शिमला संसदीय क्षेत्र की कुफरी चायल सड़क को 53 करोड़ रूपये सीआरएफ में प्राप्त हुए है। केन्द्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद की जा रही है, अन्यथा हिमाचल प्रदेश की तो यह हालात हैं कि कांग्रेस सरकार सैलरी और पेंशन देने की स्थिति में भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि मंदिरों का पैसा भी कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं के लिए खर्च कर रही है यह देव भूमि के लिये बहुत ही चिंतनीय एवं दुख का विषय है और इस प्रकार से पैसे को उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। हाल ही में भाजपा द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया था कि केन्द्र सरकार के पैसे को हिमाचल की विभिन्न योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और यह आरोप लगातार सिद्ध होता दिखाई दे रहा है।

प्रदेश की बजाये

.....पृष्ठ 1 का शेष

है और अपने मित्रों को सहूलियतें दी हैं। डीजल पर छः रुपए की वृद्धि करके सरकार ने किस प्रकार से प्रदेशवासियों का भला किया? आपदा में अपने मित्रों के अलावा सबके क्रशर बंद करवाकर, प्रदेश के लोगों की बिजली की सब्सिडी छीनकर, डिपुओं में मिलने वाले राशन को महंगा करके, तेल की सप्लाई महीनों रोककर, अनाजों की संख्या कम करने, लोगों को नौकरी से निकालने, पूरे आत्मविश्वास से झूठ बोलने के अलावा सुक्खू सरकार की उपलब्धि क्या है?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंदिरों से मदद करने का आधिकारिक दस्तावेज पूरे देश ने देखा, मंदिरों में हुई ट्रस्ट की बैठकों खबरें हर अखबार में छपी हैं। पार्टी की अध्यक्ष कह रही हैं कि पैसा मांगा गया है, मंत्री कह रहे हैं कि मांग लिया है तो गलत क्या है? लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पैसा मांगा ही नहीं। इसका मतलब मुख्यमंत्री खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री पैसा मांगने के बाद भी झूठ क्यों बोल रहे हैं सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सरेआम इस तरह से झूठ बोलना मुख्यमंत्री की नीयत को दिखाता है। झूठ बोलने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।